

दैनिक भास्कर

.com

शनिवार



जयपुर | 30 जुलाई, 2011

श्रावण कृष्ण पक्ष-अमावस्या, 2068

एप्पल के पास अमेरिकी सरकार से ज्यादा पैसा

वित्त विभाग ने पहली बार खजाने के आंकड़े जारी किए, अमेरिका के पास 3.25 लाख करोड़ रुपए, जबकि स्टीव जॉब्स की एप्पल कंपनी के पास 3.35 लाख करोड़ नकद

न्यूयॉर्क | आर्थिक महाशक्ति अमेरिका का सरकारी खजाना खाली हो गया है। स्थिति यह है कि उसके पास जितना पैसा बचा है, उससे कहीं ज्यादा पैसा टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के पास है।

अमेरिकी वित्त विभाग ने पहली बार खजाने के आंकड़े जारी करते हुए चेतावनी दी कि उसके पास सीमित धन बचा है। यदि 2 अगस्त तक रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सदस्यों के बीच मतभेद समाप्त नहीं हुए तो आने वाले समय में वित्तीय मुश्किलें बढ़ सकती हैं। व्हाइट हाउस ने भी रिपब्लिकन सदस्यों को चेताया है कि सरकार के पास 2 अगस्त तक का खर्चा चलाने का पैसा बचा है। अमेरिकी सरकार के खजाने में 73.76 अरब डॉलर (3.25 लाख करोड़ रुपए) की राशि है। वहीं एप्पल के पास 75.87 अरब डॉलर (3.35 लाख करोड़ रुपए) की नकद राशि है। **शेष | पेज 6**

एप्पल 4 साल में बना अमीर

दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के पास 75.87 अरब डॉलर नकद हैं। बाजार में उसकी कुल पूंजी 363.25 अरब डॉलर है। उसने 2007 से तरक्की शुरू की। इसी साल आईफोन लांच किया था। तीन साल में एप्पल, ब्लैकबेरी बनाने वाली कंपनी रिसर्च इन मोशन (आरआईएम) से भी आगे निकल गई।

शेयर बाजार में भी धाक : स्टीव जॉब्स की एप्पल कंपनी का एक शेयर 400 डॉलर का है। एप्पल के बाद माइक्रोसॉफ्ट है, जिसके पास 40 अरब डॉलर नकद राशि है।



अमेरिका में क्यों बढ़ा कर्ज संकट?

- अमेरिकी खर्चों में वृद्धि हुई, इसकी तुलना में टैक्स कम मिला।
- अमेरिका पिछले दस सालों में अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई पर 3.7 लाख करोड़ डॉलर खर्च कर चुका है।
- इस खर्च में 4.4 लाख करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी का अनुमान है।
- वार्षिक बजट घाटा 1.50 खरब डॉलर है।

क्यों जरूरत है कर्ज की?

- सरकार कर्ज के पैसों से नियमित खर्चों का भुगतान करती है।
- इनमें सेना की तनख्वाह, कर्ज पर ब्याज की रकम और स्वास्थ्य सुविधाओं पर होने वाला खर्च शामिल है।

साख पर खतरा

- कर्ज भुगतान नहीं किया तो साख प्रभावित होगी, क्रेडिट कार्ड, कार और मकान के लिए मिलने वाले कर्ज की दरें तेजी से बढ़ेंगी।
- विदेशी कर्जदाता अमेरिकी बैंकों से पैसा वापस निकालने लगेंगे।
- कर्ज चुकाने के मामले में 'ट्रिपल ए' रेटिंग खतरे में पड़ जाएगी।

भास्कर एमएसएमई नॉलेज फोरम



शुक्रवार को जयपुर के महावीर स्कूल सभागार में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों (एमएसएमई) पर दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित नॉलेज फोरम में लोगों के सवाल का जवाब देते (बाएं से) एसबीबीजे के एमडी शिवकुमार, रीको के एमडी राजेंद्र भानावत, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्र सरकार के सचिव (एमएसएमई) उदय वर्मा, राजस्थान के प्रमुख सचिव (लघु उद्योग) अशोक सिंघवी, वैश लॉ एंजोसिएट्स दिल्ली के हितेंद्र मेहता और मयूर लेदर प्रोडक्ट्स के आरके पोद्दार। (खबर पेज 2)

एक अगस्त से